Deccan Chronicle - 13 March-2024

Won't release water to TN without retaining for consumption: K'taka CM

Chamarajanagar, March 12: Karnataka Chief Minister Siddaramaiah on Tuesday dismissed as a lie the opposition BJP's charge that Cauvery water is being released to Tamil Nadu even though Bengaluru is reeling under an acute water crisis.

Terming it a lie, Siddaramaiah said not a single drop of water will be given to Tamil Nadu. "All that is lie. Who will let the water flow, that too in this situation? We will not give even a drop of water to Tamil Nadu without retaining water for our consumption," the Chief Minister told reporters here.

He said that neither Tamil Nadu asked for it nor anyone directed Karnataka to release water to the neighbouring state. "Why will we give them (Tamil Nadu) water when they have not asked for it? Where do we have water to give them? There is no question of giving them (TN) water even if Tamil Nadu asks for it or the Centre or anyone else directs us to release water," Siddaramaiah said.

The Leader of Opposition R Ashoka on Monday accused the Karnataka government of having released Cauvery water to Tamil Nadu. He demanded that the state government immediately stop releasing water to the neighbouring state and respond to the plight of the people of Bengaluru. —*PTI*

Hindustan Times - 13 March -2024

जल का दोबारा उपयोग करने में कर्नाटक अव्वल

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। इस्तेमाल हो चुके पानी का पुनः उपयोग करने में हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और राजस्थान आगे हैं। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, शहरों में पानी की बढ़ती मांग और घटते भूजल स्तर के साथ, देशभर में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के स्तर पर गैर-पेयजल उद्देश्यों के लिए यूज्ड वॉटर ट्रीटमेंट और रियूज को बढ़ाना जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अभी 90 प्रतिशत यूएलबी में यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट के लिए लक्षित वित्तीय नियोजन और निवेश की कमी एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। यह रिपोर्ट 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की उन 503 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) पर केंद्रित है, जिन्होंने ट्रीटेड यूज्ड वॉटर रियूज नीतियों को अपनाया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश के 7200 करोड़ लीटर 'यूज्ड वॉटर' में से 28 प्रतिशत का ट्रीटमेंट होता है। यूज्ड वॉटर ट्रीटमेंट को मजबूत बनाने और रियूज को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की जरूरत है। इसे देखते हुए सीईईडब्ल्यू रिपोर्ट ने अपनी तरह का पहला म्युनिसिपल यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट(एमयूडब्ल्यूएम) इंडेक्स तैयार किया है।

ये रहे नतीजे

यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट के लिए समर्पित कार्य योजनाओं और बुनियादी ढांचे व दक्षता जैसे क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के साथ सूरत नगर निगम और बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका 'उत्कृष्ट' प्रदर्शन करने वाले यूएलबी के रूप में सामने आए हैं। श्रेणीबद्ध कार्य योजनाओं के साथ हरियाणा और कर्नाटक को अग्रणी राज्यों के रूप में चिह्नित किया है।

Dainik Bhaskar- **13 March -2024**

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में सीएम योगी बोले-

हर घर, नल से जल, पीएम मोदी की गारंटी 2.12 करोड़ परिवारों को मिला शुद्ध पेयजल

एजेंसी ▶▶ लखनऊ

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 'हर घर, नल से जल' के संकल्प के साथ प्रदेश के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाभियान चल रहा है।

जल जीवन मिशन के प्रारंभ से पूर्व मात्र 5.16 लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। लगातार प्रयासों से आज 2 करोड़ 12 लाख से अधिक परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ है। शेष घरों को भी पाइप्ड पेयजल की सुविधा मिले, ऐसे में इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए।

> जल जीवन मिशन की समीक्ष बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए की पाइप से पेयजल की सुविधा मिले, ऐसे में इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने विंध्य-बुंदेलखंड के लिए विशेष प्रबंध करने का भी निर्देश दिया।

खास बातें

- 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराएंगे
- विंध्य-बुंदेलखंड में शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ
- जल संरक्षण के लिए लोगों को करें जागरूक
- हर गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर तैनात करें

11 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण

सीएम योगी ने शहरी विकास से जुड़ी 11,000 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में नगर विकास विभाग की ओर से संचालित 22 योजनाओं के तहत शहरों के विकास से संबंधित 9458.66 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली 3150 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और 1632.58 करोड़ की लागत से तैयार हो चुकी 269 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी ने कहा कि यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर शहरों के विकास के लिए योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है। आज यूपी अपनी विरासत को सहेजते हुए विकास कर रहा है। जनता को बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

विंध्य-बुंदेलखंड के लिए विशेष प्रबंध करें

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह योजना ईज ऑफ लिविंग के संकल्प को पूरा होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बड़े बदलाव का परिचायक है। यह मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में शुद्ध पेयजल एक सपना था। आज यह सपना साकार हो रहा है। यह दोनों ही क्षेत्र शीर्ष प्राथमिकता में है। अतिशीघ्र विंध्य-बुंदेलखंड के हर घर में नल से जल की सुविधा होगी। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मीरजापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य-बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन का कार्य आखिरी चरण में प्रवेश कर गया है।

यूपी को मिली 3 नई वंदे भारत, एक का विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए 10 वंदे ट्रेनों का लोकार्पण किया। चार वंदे भारत का विस्तार किया। इनमें से तीन वंदे भारत यूपी को मिली। इनमें पीएम ने लखनऊ-देहरादून, पटना-लखनऊ और रांची-वाराणसी के लिए भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वहीं, गोरखपुर-लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का एक्सटेंशन प्रयागराज तक किया गया है। लखनऊ-देहरादून के बीच 19 मार्च से वंदेभारत शुरू हो सकती है। विस्तार हुई वंदे भारत में गोरखपुर से लखनऊ आने वाली वंदे भारत प्रयागराज तक चलेगी। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद का लखनऊ, आलमनगर सहित 22 स्टेशनों पर लोकार्पण किया।

योगी ने जताया आभार

सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी का आभार जताते हुए लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राष्ट्र के विकास को रफ्तार देतीं 85 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल परियोजनाओं के लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से सहभाग किया। 'विकसित भारत' के नवनिर्माण को विस्तार देतीं इन सौगातों के लिए प्रधानमंत्री का आभार।